



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 419]

नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 21, 2008/कार्तिक 30, 1930

No. 419]

NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 21, 2008/KARTIKA 30, 1930

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय)

जांच शुरुआत संबंधी अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 नवम्बर, 2008

निर्णायक समीक्षा

विषय : चीन जनवादी गणराज्य के मूल के अथवा वहाँ से निर्यातित मेलामाइन के आयातों पर लागू पाटनरोधी शुल्क की निर्णायक समीक्षा की शुरुआत ।

सं. 15/29/2008-डीजीएडी.—यतः वर्ष 1995 में यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 और सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर शुल्क अथवा अतिरिक्त शुल्क का आकलन और वसूली तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे एतदपश्चात् पाटनरोधी नियमावली कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए निर्दिष्ट प्राधिकारी ने दिनांक 27.2.2004 की अधिसूचना सं. 14/16/2003-डीजीएडी के तहत अनंतिम शुल्क लगाने की सिफारिश की थी और दिनांक 2.4.2004 की अधिसूचना सं. 53/2004-सीमाशुल्क के तहत भारत सरकार द्वारा यह अनंतिम शुल्क लगाया गया था । प्राधिकारी ने चीन जन. गण. के मूल के अथवा वहाँ से निर्यातित मेलामाइन (जिसे एतदपश्चात् संबद्ध वस्तु कहा गया है) के आयातों पर निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश करते हुए अपने अंतिम जांच परिणाम दिनांक 03.09.2004 की अधिसूचना सं. 14/16/2003-डीजीएडी के तहत जारी किए और दिनांक 16 नवम्बर, 2004 की सीमाशुल्क अधिसूचना सं. 107/2004-सीमाशुल्क के तहत भारत सरकार द्वारा यह निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाया गया था ।

2. समीक्षा तथा जाँच की शुरुआत हेतु अनुरोध

और यतः ऊपर उल्लिखित अधिनियम तथा नियमावली के अनुसार लगाया गया पाटनरोधी शुल्क, लागू किए जाने की तारीख से पाँच वर्ष की अवधि की समाप्ति पर निष्प्रभावी हो जाएगा जब तक कि

निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें एतदपश्चात् प्राधिकारी कहा गया है) समीक्षा द्वारा यह निर्धारित न करें कि शुल्क की समाप्ति से पाटन तथा घरेलू उद्योग को क्षति जारी रहेगी अथवा उसकी पुनरावृत्ति होगी।

और यतः उपर्युक्त प्रावधानों के अनुसार, घरेलू उद्योग अर्थात् मै. गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर्स एंड कैमिकल लि., वड़ोदरा ने निर्दिष्ट प्राधिकारी से ऐसी समीक्षा का अनुरोध करते हुए एक आवेदन के साथ सम्पर्क किया था। प्राधिकारी का विचार है कि पाटनरोधी शुल्क के संबंध में निर्णायक समीक्षा की कार्यवाही की शुरुआत इस बात की जांच करने के लिए उचित होगी कि क्या शुल्क समाप्त किए जाने की स्थिति में पाटन तथा क्षति के जारी रहने अथवा उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है। माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने वर्ष 2006 की रिट याचिका सं. 16893 में कहा था कि निर्णायक समीक्षा अनिवार्य है। इसलिए प्राधिकारी पाटनरोधी नियमावली के नियम 23 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9क(5) के अनुसार निर्णायक समीक्षा की शुरुआत करते हैं।

3. समीक्षा के आधार

पाटनरोधी शुल्क को जारी रखने संबंधी अनुरोध इस आधार पर किया गया है कि संबद्ध वस्तुओं के आयात में सापेक्ष रूप से वृद्धि हुई है। इसके अतिरिक्त आयातों की सापेक्ष मात्रा भारतीय सीमाशुल्क विभाग के आंकड़ों में प्रदर्शित मात्रा से बहुत अधिक है। भारत में कुल आयातों की तुलना में चीनी आयातों में वृद्धि हुई है। याचिकाकर्ता ने सूचित किया है कि आयात कीमत में भी वृद्धि हुई है किंतु यह वृद्धि घरेलू बिक्री कीमत से बहुत कम है। याचिकाकर्ता ने आगे यह तर्क दिया कि कीमतों यह वृद्धि निविष्टि लागतों में वृद्धि के कारण हुई थी। तथापि शुल्क की समाप्ति की स्थिति में घरेलू उद्योग को क्षति की संभावना है। अतः याचिकाकर्ता ने कहा है कि पाटनरोधी शुल्क समाप्त किए जाने की स्थिति में पाटन तथा घरेलू उद्योग को क्षति होने की संभावना है।

4. विचाराधीन उत्पाद

मूल जाँच में विचाराधीन उत्पाद मेलामाइन था जो एक स्वादरहित, गंधरहित तथा विषरहित पदार्थ (रासायनिक चूर्ण) है। सौंदर्य तथा उपयोगिता संबंधी अनेक उत्पादों को बनाने के लिए फॉर्मेलिहाइड के साथ मेलामाइन की अभिक्रिया की जाती है और उसे राल अथवा मोल्लिंग चूर्ण का रूप दिया जाता है। लैमिनेट्स के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला मेलामाइन फॉर्मेलिहाइड काफी कठोर तथा खरोंच, दाग, जल और ऊष्मा का प्रतिरोधी होता है। कुल इलेक्ट्रिकल अनुप्रयोगों में इस्तेमाल होने वाले लैमिनेट में उच्च मशीनी सुदृढ़ता, अच्छी ऊष्मा प्रतिरोधात्मकता तथा विद्युत्तरोधी गुणधर्म होते हैं। मेलामाइन सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के अध्याय 29 के सीमाशुल्क उपशीर्ष सं. 293361 तथा आईटीसी (एचएस) कोड 29336100 के अंतर्गत वर्गीकृत है। तथापि यह वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और किसी भी रूप में मौजूदा जाँच के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है।

5. निर्यात के देश में सामान्य मूल्य

आवेदकों ने अनुरोध किया है कि चीन जन. गण. गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश है और सभी जाँचों में इस प्राधिकारी द्वारा इसे ऐसा ही माना गया है, जो अलग-अलग निर्यातकों द्वारा इस अवधारणा के खंडन के अध्वधीन है। तदनुसार याचिकाकर्ता ने अनुरोध किया है कि जब तक प्रतिवादी चीन के निर्यातक प्राधिकारी को संतोषजनक उत्तर नहीं देते, निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा नियमावली के अनुबंध 1 के पैरा 7 के अनुसार सामान्य मूल्य का निर्धारण अपेक्षित है। याचिकाकर्ता ने आगे यह अनुरोध किया है कि वह बाजार

अर्थव्यवस्था वाले किसी तीसरे देश में कीमत अथवा परिकलित मूल्य संबंधी जानकारी प्राप्त नहीं कर सका । तदनुसार याचिकाकर्ताओं ने चीन जन. गण. हेतु भारत को सहोदर देश मानने का प्रस्ताव किया है । तथापि, निर्यातक देश की सरकार, संबद्ध देश के निर्यातक तथा उत्पादक संबद्ध देश में सामान्य मूल्य के निर्धारण हेतु गैर-बाजार अर्थव्यवस्था के दर्जे की उपरोक्त अवधारणा का खंडन करते हुए प्रश्नावली का अलग-अलग उत्तर दायर कर सकते हैं ।

6. प्रक्रिया

- (क) **शामिल देश :** मौजूदा समीक्षा में शामिल देश चीन जनवादी गणराज्य है ।
- (ख) **जांच अवधि :** वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ जांच की अवधि 01 अप्रैल, 2007 से 30 जून, 2008 है । तथापि, क्षति जांच अवधि में वर्ष 2004-05, 2005-06, 2006-07 की अवधि तथा जांच अवधि शामिल होगी ।
- (ग) जांच में यह निर्धारित किया जाएगा कि क्या उपाय की समाप्ति पर पाटन तथा क्षति के जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है और पाटन तथा क्षति की भरपाई के लिए अपेक्षित शुल्क की राशि क्या होगी ।
- (घ) समीक्षा में दिनांक 03.09.2004 की अधिसूचना सं. 14/16/2003-डीजीएडी के सभी पहलू शामिल होंगे,
- (ङ.) उपर्युक्त नियमावली के नियम 6,7,8,9,10,11 16, 17, 18, 19 और 20 के प्रावधान आवश्यक परिवर्तनों सहित इस समीक्षा पर लागू होंगे ।
- (च) **सूचना प्रस्तुत करना :** संबद्ध देश के निर्यातकों और भारत में संबद्ध देश के दूतावास के माध्यम से उसकी सरकार, भारत में उत्पाद से संबंधित माने जाने वाले आयातकों एवं प्रयोक्ताओं तथा घरेलू उद्योग को संबंधित सूचना निर्धारित प्रपत्र में और निर्धारित ढंग से प्रस्तुत करने और अपने विचारों से निम्नलिखित को अवगत कराने के लिए अलग से लिखा जा रहा है :-

निर्दिष्ट प्राधिकारी

(पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय)

भारत सरकार

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

वाणिज्य विभाग

कमरा नं. 240, उद्योग भवन

नई दिल्ली-110011

कोई अन्य हितबद्ध पक्ष भी नीचे निर्धारित समय सीमा के भीतर तथा निर्धारित प्रपत्र में और ढंग से जांच से संगत अनुरोध कर सकता है ।

- (छ) **समय सीमा :** वर्तमान समीक्षा से संबंधित कोई भी सूचना तथा सुनवाई के लिए कोई अनुरोध लिखित रूप में भेजा जाए, जो निर्दिष्ट प्राधिकारी को इस समीक्षा अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से चालीस (40) दिन के भीतर उपर्युक्त पते पर प्राप्त हो जाना चाहिए । यदि निर्धारित अवधि के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है अथवा अधूरी सूचना प्राप्त होती है, तो निर्दिष्ट प्राधिकारी, उपर्युक्त नियमावली के अनुसार रिकार्ड में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने परिणाम दर्ज कर सकते हैं ।

(ज) अगोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना : नियमावली के नियम 6(7) के अनुसार हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्राधिकारी को प्रदत्त गोपनीय सूचना का अगोपनीय सारांश प्रस्तुत करना अपेक्षित है और यदि ऐसी सूचना देने वाले पक्षकार की राय में ऐसी सूचना का सारांश नहीं बनाया जा सकता है तो उसके कारणों का विवरण प्रस्तुत करना अपेक्षित है। यदि कोई हितबद्ध पक्षकार आवश्यक सूचना प्रस्तुत करने से मना करता है अथवा उचित अवधि के भीतर अन्यथा प्रस्तुत नहीं करता है या जांच में अत्यधिक बाधा डालता है, तो प्राधिकारी अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं और केन्द्रीय सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं।

(झ) सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण : नियम 6(7) के अनुसार कोई भी हितबद्ध पक्षकार अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के अगोपनीय रूपांतरण वाली सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण कर सकता है।

(ञ) उपलब्ध तथ्यों का उपयोग : यदि कोई हितबद्ध पक्षकार आवश्यक सूचना जुटाने से मना करता है अथवा उचित अवधि के भीतर अन्यथा उसे प्रस्तुत नहीं करता है या जांच में अत्यधिक बाधा डालता है, तो प्राधिकारी अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं और केन्द्रीय सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं।

आर. गोपालन, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF ANTI-DUMPING AND ALLIED DUTIES)

INITIATION NOTIFICATION

New Delhi, the 21st November, 2008

SUNSET REVIEW

Subject : Initiation of Sunset Review of anti-dumping duty imposed against import of Melamine originating in or exported from China PR.

F.No. 15/29/2008-DGAD.—Whereas, the Designated Authority having regard to the Customs Tariff Act, 1975 as amended in 1995 (hereinafter referred to as the Act) and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Duty or Additional Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 (hereinafter referred to as AD Rules) recommended imposition of provisional duty vide notification No.14/16/2003-DGAD dated 27.02.2004 and such provisional duty was imposed by the Government of India vide Notification No.53/2004-Customs dated 02.04.2004. The Authority issued its final findings recommending imposition of definitive anti dumping duty on imports of Melamine (hereinafter referred to as subject goods) originating in or exported from China PR, vide notification Number 14/16/2003-DGAD dated 03.09.2004 and such definitive duty was imposed by the Govt. Of India vide customs notification No.107/2004-Customs dated 16th November, 2004.

2. Request for Review and Initiation

AND WHEREAS in terms of the Act and Rules referred to above the anti dumping duty imposed shall cease to have effect on expiry of five years from

the date of such imposition unless the Designated Authority (hereinafter referred to as the Authority) in a review determines that expiry of the duty shall lead to continuation or recurrence of dumping and injury to the domestic industry.

AND WHEREAS in terms of the above provisions, the domestic industry i.e. M/s Gujarat State Fertilizers & Chemical Ltd., Vadodra approached the Designated Authority with an application requesting for such a review. The Authority considers that initiation of Sunset Review proceedings for the anti dumping duty in force would be appropriate to examine whether the expiry of duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury. The Hon'ble Delhi High Court in W.P. No.16893 of 2006 held that sunset review is mandatory. Therefore, the Authority, hereby, initiate sunset review in accordance with Section 9A(5) of the Act read with Rule 23 of anti dumping Rules.

3. Grounds for review:

The request is for continuation of the antidumping duties is based on the grounds that import of subject goods has increased in absolute terms. Further, the absolute volume of imports is far higher than what is reflected in the Indian custom data. The share of the Chinese imports has increased as compared to total imports in India. Petitioner has stated that even import price have increased, but the increased in import price is far lower than the domestic selling price. Petitioner further argued that increase in prices was a result of increase in the input costs. The injury to the domestic industry is however likely in the event of revocation of duties. The petitioner has thus alleged that dumping and consequent injury to the domestic industry is likely in the event of revocation of anti dumping duties.

4. Product under consideration

The product under consideration in the original investigation was. Melamine , a tasteless, odorless, and non- toxic substance (chemical powder). Melamine is reacted with format dehyde and made into resins or moulding powder for making innumerable products of beauty and utility. Melamine formaldehyde resin used for laminates offer good hardness, resistance to scratch, stain, water and heat. Laminate used in some electrical applications possess high mechanical strength, good heat resistance and good electrical insulating properties.. Melamine is classified under customs sub-heading no. 293361 under Chapter 29 of the Customs Tariff Act, 1975 and ITC (HS) Code 29336100. The classification is however indicative only and in no way binding on the scope of the present investigations.

5. Normal value in the country of export

The applicant has submitted that Chine PR continues as a non market economy country and have been treated so by the Authority in all investigations subject to rebuttal of the presumption by individual exporters. Accordingly, the petitioner has submitted that unless the responding Chinese exporters satisfies the Authority, the Designated Authority is required to

determine normal value in accordance with para 7 of Annexure 1 to the Rules. The petitioner has further submitted that they could not obtain the information on price or constructed value in a market economy third country. Accordingly the petitioners has proposed India as a surrogate country for China PR. However, the Govt of exporting country, exporters and producers from the subject country may file separate questionnaire response rebutting the above presumption of non market economy status for determination of normal value in the subject country.

6. Procedure

- a) **Countries involved:** the country involved in the present review is the Peoples Republic of China.
- b) **Period of investigation:** the period of investigation for the purpose of the present investigations is 1st April, 2007 to 30th June, 2008. The injury investigation period would however cover the period 2004-05, 2005-06, 2006-07 and the POI.
- c) The investigation will determine whether the expiry of the measure would be likely to lead to a continuation or recurrence of dumping and injury and the quantum of duty required for offsetting dumping and injury.
- d) The review will cover all aspects of Notification No.14/16/2003-DGAD dated 03.09.2004.
- e) The provisions of Rules 6 7 8 9 10 11 16 17 18 19 and 20 of the Rule supra shall be mutatis mutandis applicable in this review.
- f) **Submission of information** The exporters in the subject country, the governments of the subject country through its embassy in India, the importers and users in India known to be concerned with the product and the domestic industry are being addressed separately to submit relevant information in the form and manner prescribed and to make their views known to the authority at the following address:

Designated Authority
(Directorate General of Anti Dumping and Allied Duties)
Government of India
Ministry of Commerce & Industry
Department of Commerce
Room No.240, Udyog Bhawan
New Delhi-110 011.

Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation in the prescribed form and manner within the time limit set out below.

- g) **Time limit** – Any information relating to the present review and any request for hearing should be sent in writing so as to reach the authority at the address mention above not later than forty days(40 days) from the date of publication of this review notification. If no information is received within the prescribed time limit or the information received is incomplete, the Designated

Authority may record its findings on the basis of the facts available on record in accordance with the Rules supra.

- h) **Submission of information on Non confidential basis** – in terms of rule 6(7) of the Rules the interested parties are required to submit non confidential summary or any confidential information provided to the authority and if in the opinion of the party providing such information such information is not susceptible to summarization a statement of reason thereof is required to be provided. In case where an interested party refuses access to or otherwise does not provide necessary information within a reasonable period; or significantly impede the investigation the Authority may record its findings on the basis of facts available to it and make such recommendations to the central government as deemed fit.
- i) **Inspection of public file:** in terms of Rule 6(7) any interested party may inspect the public file containing non confidential version of the evidence submitted by other interested parties.
- j) **Use of the facts available:** in case where an interested party refuses access to or otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation the Authority may record its findings on the basis of facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

R. GOPALAN, Designated Authority